RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : रविवार 29 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 187 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई में इंसान बना दरिंदा...

कुत्ते को बनाया हवस का शिकार, कैसे सामने आया मामला?

नवी मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी से सटे नवी मुंबई में एक व्यक्ति द्वारा आवारा कुत्ते से संबंध बनाने का मामला सामने आया है. शारीरिक शोषण के मामले में पुलिस ने 43 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एक हाउसिंग सोसायटी के अंदर उसने इस घटना को अंजाम दिया. इस व्यक्ति की पहचान संजय कदम के रूप में हुई है. वो पेशे से लेबर है. कोपर खैराने थाना पुलिस ने उसपर आईपीसी की धारा 377 (आप्रकृतिक यौनाचार) और जानवरों के खिलाफ क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना बीते माह 28 सितंबर की है. हाउसिंग सोसायटी के ग्राउंड फ्लोर पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया. मामले की जानकारी पुलिस को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दी. उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जा सका. यह युवक इस वक्त न्यायिक हिरासत में है.

जरांगे की सरकार को चेतावनी...

29 अक्तूबर से महाराष्ट्र के हर गांव में शुरू करेंगे भूख हड़ताल

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इस बीच, शनिवार को उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह तत्काल आरक्षण देने में विफल रहती है तो 29 अक्तूबर से महाराष्ट्र के हर गांव में सिलसिलेवार भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए जरांगे ने एलान किया कि आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और तीसरा चरण 31 अक्तूबर को शुरू होगा। भूख हड़ताल के चौथे दिन जालना के जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल और पुलिस अधीक्षक शैलेश ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की, जिसके बाद जरांगे (40 वर्षीय) ने डॉक्टरों से जांच कराने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 29 अक्तूबर से महाराष्ट्र के हर गांव में सिलसिलेवार भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। सरकार को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए और आंदोलनकारी मराठों के मजबूत संकल्प को कम करने नहीं आंकना चाहिए। जरांगे ने 25 अक्तूबर को अपनी भूख हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया, जिसके एक दिन बाद ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त हो गया। उन्होंने उसी गांव में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक 14 दिनों तक उपवास रखा था और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन पर इसे वापस ले लिया था।

'मुंबई को कमजोर करने का प्रयास कर रही बीजेपी, सिर्फ शिवसेना ही...'

उद्धव ठाकरे का आरोप

मुंबई : शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मुंबई के महत्व को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और सभी व्यापार और उद्योगों को गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है. शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ही महाराष्ट्र में बीजेपी को रोक सकती है. उद्धव ठाकरे ने कहा, ''मैं संकट यानी शिवसेना के विभाजन के बाद में भी अवसर देखता हूं.'' उन्होंने शिवसेना की पहली पीढ़ी के कार्यकताओं से युवा कार्यकताओं को मुंबई, महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए पार्टी की अपरिहार्यता के बारे में बताने की अपील की. पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर मुंबई के महत्व को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

बीएमसी के धन से कराया जा रहा है निर्माण-ठाकरे

ठाकरे ने सवाल किया, ''सभी व्यापार और उद्योगों को गुजरात स्थानांतरित किया जा रहा है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत थी?'' ठाकरे ने कहा कि तटीय मार्ग का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम के धन से कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिवसेना की लड़ाई निरंकुश प्रवृत्ति से है न कि लोगों से. ठाकरे ने आरोप लगाया, ''2014 और 2019 में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन अब उसने शिवसेना जो 2022 में एकनाथ शिंदे की तरफ से पार्टी में टूट का संदर्भ को लूट लिया और उसे खत्म करने का प्रयास किया'' उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें 2014 में बताया था कि जब शिवसेना (अविभाजित) एक महीने के लिए विपक्ष में थी तब गठबंधन टूट गया था क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती थी. ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व पर बीजेपी का विशेषाधिकार नहीं है. उन्होंने कहा, ''मैं अभी भी लोगों से कहता हूं कि अगर वह शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जीत का श्रेय विश्वासघात की मानसिकता वाले लोग लें.''

'मैं वापस आऊंगा' वीडियो को लेकर पटोले का फडणवीस पर तंज,

बोले- लोगों ने उन्हें दिलों से हटा दिया...

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। हालांकि, कुछ घंटों बाद इसे हटा दिया। इस वीडियो में वह कहते हुए दिखाई दे रहे थे- 'मैं वापस आऊंगा'। अब इसको लेकर राज्य की सियासत गरमा गई हैं। एक दिन बाद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने इस वीडियो क्लिप को लेकर तंज कसा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था- मैं वापस आऊंगा। इस टिप्पणी के कारण सोशल मीडिया पर उनके कई मीम बनने लगे। वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए पटोले ने कहा कि भाजपा को इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जनता पहले ही उन्हें (फडणवीस) अपने दिलों से हटा चुकी है। पटोले ने दावा किया कि फडणवीस भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पक्ष में नहीं हैं, जबकि लोगों ने झूठ बोलने वालों की पार्टी पर भरोसा करना बंद कर दिया है। पटोले ने दावा किया, सोशल मीडिया का महत्व बढ़ गया है। किसी को ट्वीट (एक्स पर वीडियो क्लिप) की प्रतिक्रियाओं को देखना चाहिए।

लोगों ने कहा है कि वे भाजपा को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। शुक्रवार की घटना ने राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलों को जन्म दे दिया है, खासकर तब जब विधानसभा अध्यक्ष पिछले साल जून में शिवसेना के विभाजन के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कई विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। पटोले ने यह भी कहा कि केले और कपास की खेती करने वाले किसान परेशान हैं और राज्य सरकार को उन्हें तत्काल राहत प्रदान करनी चाहिए। जलगांव में संवाददाताओं से बातचीत में पटोले ने किसानों और बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की। उन्होंने दावा किया, राज्य सरकार एक रुपये में फसल बीमा देने का दावा करते हुए अपना ढिंढोरा पीट रही है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

शहरी गरीबी से निपटना...

शहरी माहौल के जटिल सवालों के बीच एक अकाट्य सत्य मौजूद है- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र लंबे समय से शहरों की गरीबी से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। लिहाजा, अगर हम वाकई शहरी गरीबी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमें अपने शहरों के अक्सर नजरअंदाज किए गए चेहरों को समझने के लिए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस (जुलाई 2022 से जून 2023 तक) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान श्रम बल की भागीदारी दर 42.4 प्रतिशत पर अनुमानित थी। 15 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गणना 60.8 प्रतिशत तो शहरी इलाकों में 50.4 फीसदी की गई। श्रमबल की और गहराई से विवेचना करें तो कामगार जनसंख्या अनुपात या डब्ल्यूपीआर (प्रति1,000 लोगों पर रोजगार के आंकड़े के रूप में परिभाषित) हमें देश के रोजगार हालात के बारे में एक संकेत देता है। इस अवधि के दौरान भारत में 15 वर्ष और अधिक के लोगों के लिए डब्ल्यूपीआर 56 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 59.4 फीसदी और शहरी इलाकों में 47.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर पूरे देश के लिए जहां 3.2 प्रतिशत रही, वहीं शहरी क्षेत्र के लिए यह 5.4 प्रतिशत थी। ये आंकड़े हमें श्रम बाजार की एक झलक देते हैं, खास तौर पर शहरी संदर्भ में। पीएलएफएस से हमें शहरी श्रमबल में स्वरोजगार, आकस्मिक और नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के प्रतिशत हिस्से के आंकड़ों के रूप में मदद मिलती है। यह संकेतक हमें श्रम बाजार के भीतर किस सीमा तक अनौपचारिकता है, इसकी जानकारी भी मुहैया कराता है (स्वरोजगार में लगे कामगारों के प्रतिशत हिस्से के रूप में)। इस हिसाब से स्वरोजगार में लगे श्रमबल का प्रतिशत हिस्सा 39.6 फीसदी होने का अनुमान था।

स्वरोजगार की श्रेणी में दोनों तरह के लोग शामिल हैं, वे जो खुद का काम करते हैं या किसी के साथ काम करते हैं (स्ट्रीट वेंडर समेत) और वे जो घर के काम में मदद करते हैं। शहरी गरीबी और अनौपचारिकता एक दूसरे से जुड़े ऐसे कारक हैं जहां श्रम अनौपचारिक रूप से श्रमबल को भीषण गरीबी में धकेलता है। गरीबी और असमानता बने रहने का यही एकमात्र कारण नहीं है लेकिन इसका महत्त्वपूर्ण योगदान जरूर है। अनौपचारिक शब्द का उपयोग रोजगार की विभिन्न स्थितियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसमें घर पर किए गए काम से लेकर प्रतिकूल कार्य स्थितियां समेत हर चीज शामिल है। लाभ न मिलना और लघु उद्योगों से जुड़ा होना, ये सब असुरक्षा के स्तर के बारे में बताते हैं। अनौपचारिकता में वे आर्थिक गतिविधियां भी शामिल की जा सकती हैं जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं हैं या जिनकी सूचना नहीं मिलती। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र महज एक चलताऊ विचार नहीं है, इसमें बदलाव लाने की क्षमता है। रोजगार सृजन में इसके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, खासतौर पर उनके लिए जो गरीबी की कड़वी सचाइयों से रू-ब-रू हैं। रोजगार उपलब्ध कराने और आय सृजन की इसकी क्षमता के जरिये यह क्षेत्र पहले से ही गरीबी की भयावहता और दायरा घटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन यह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अनौपचारिक क्षेत्र को और सक्षम बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा ताकि इनका ज्यादा असर हो। अनौपचारिक काम में लगे लोगों का आय स्तर बढ़ाने और रोजगार सृजन में इसकी क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। शहरी गरीबी उन्मूलन रणनीति में यही सबसे प्रमुख होना चाहिए। इस रणनीति के तहत हम महज एक ही मसले से नहीं निपट रहे हैं बल्कि ज्यादा समान और समृद्ध शहरी भविष्य की नई राह बना रहे हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मराठा आरक्षण की मांग, 9 दिन में 11 सुसाइड:

महाराष्ट्र सरकार की कमेटी 24 दिसंबर को रिपोर्ट देगी, मराठा नेता बोले- आरक्षण के विरोध में सरकार

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को 2 और लोगों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि बीड़ जिले के शत्रुघ्न काशिद और उस्मानाबाद जिले के बलिराम देवीदास साबले ने आत्महत्या की है। राज्य में पिछले 9 दिनों में अब तक 11 लोग अपनी जान दे चुके हैं। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जारांगे ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार आरक्षण के विरोध में हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है। शिंदे सरकार ने 7 सितंबर को मराठा आरक्षण पर एक कमेटी बनाई, जिसे रिटायर्ड जज संदीप शिंदे लीड कर रहे हैं। कमेटी को रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दी गई है।

सुसाइड से पहले मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए

बीड़ जिले के अंबाजोगई तहसील के रहने वाले 27 साल के शत्रुघ्न काशिद शुक्रवार को रात करीब साढ़े 11 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने दो घंटे तक मनोज जारांगे और आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। वो सुसाइड करने जा रहा था। लोगों की सूचना पर जारांगे ने काशिद से बातचीत भी की। पुलिस ने भी उसे मनाने की कोशिश की। कुछ देर बाद काशिद ने पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद सुबह लोगों ने काशिद का शव शिवाजी की प्रतिमा के पास रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 5 मराठा गांवों और बारामती मराठा क्रांति मोर्चा ने भूख हड़ताल शुरू की और कहा कि नेता यहां न आएं।

आरक्षण नहीं मिलने से बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें

खुदकुशी का दूसरा मामला उस्मानाबाद जिले के परांडा तहसील के डोमगांव का है। पेशे से किसान 47 साल के बलिराम देवीदास साबले ने शुक्रवार को अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के मुताबिक, साबले शुक्रवार को सुबह अपने भतीजे के साथ मराठा आरक्षण पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलने से बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें। इसके बाद साबले सुबह 10 बजे अपने घर से निकले। दोपहर तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी हीराबाई उन्हें ढूंढने खेत की ओर गई। जब वे अपने खेत पहुंची तो उन्होंने साबले का शव पेड़ पर लटकते हुए देखा।

इसी हफ्ते निकलेगा नया टेंडर

शहर के ठेकेदार को रद्द करने का मनपा लेगी निर्णय

मुंबई : मनपा प्रशासन ने मुंबई शहर इलाको में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का दिए गए ठेके में ठेकेदार का ठेका रद्द कर नया ठेकेदार नियुक्त करने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है इस तरह की जानकारी मनपा के आधिकारिक सूत्रों ने दी है। शहर इलाके की सड़को का सीमेंट कंक्रीट करने का काम जिस ठेकेदार को दिया है वह काम नहीं शुरू कर पाया है जिसको लेकर मनपा ने नोटिस दिया था जिसकी समय सीमा खत्म हो गई है। मनपा अब नया ठेकेदार नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। बता दे कि 2022 में मानसून के दौरान सड़को पर बनने वाले गढ्ढों की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई की सभी सड़को को सीमेंट कंक्रीट करने का निर्देश दिया। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने 400 किमी सड़क को सीमेंट करने का निर्णय लिया। मुंबई में लगभग दो हजार किमी सड़क का जाल बिछा है। मनपा अब तक लगभग 1200 किमी सड़क को सीमेंट कंक्रीट कर चुकी है। मनपा ने बकाया 800 किमी सड़क में से 400 किमी सड़क का सीमेंट कंक्रीट करने का ठेका निकाला था जिसके लिए 5 ठेकेदारों ने मुंबई के शहर और उपनगर के कामो को लेकर ठेका लिया। मुंबई की 400 किमी सड़क में कुल 212 सड़को को सीमेंट कंक्रीट किया जाना है जिसमे मुंबई शहर की 26 सड़के शामिल थी। इन कामो को 2023 मानसून पूर्व ही शुरू किया जाना था लेकिन मानसून बीतने के बाद भी ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने पर मनपा ने 15 दिन की नोटिस दी थी जिसकी भी समय सीमा 26 अक्टूबर को खत्म हो गई। ठेकेदार ने मनपा की नोटिस का जवाब देते हुए मनपा से सुनवाई की मांग की है लेकिन मनपा के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनपा ठेकेदार को और अधिक समय न देने का निर्णय लिया है और ठेका रद्द कर नया टेंडर निकालने का निर्णय लिया है।

आदित्य ठाकरे ने कराई थी सचिन वझे की नियुक्ति

उद्योग मंत्री उदय सामंत का आरोप

मुंबई : राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में मौत के आरोप में पुलिस सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वझे को तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की सिफारिश पर फिर से पुलिस सेवा में शामिल किया गया था। एक्स पर उदय सामंत ने लिखा कि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सचिन वझे को वापस सेवा में लाने की सिफारिश की थी। उसके बाद सचिन वझे ने फरवरी 2021 में भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक परिवार के आवास के नीचे जिलेटिन की छड़ें, विस्फोटक से भरी एक कार रखी थी। वझे का सांसद संजय राऊत ने समर्थन किया था और उसे ईमानदार और सक्षम बताया था। सामंत ने कहा कि यह महाराष्ट्र के व्यापारिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका थी और राज्य से उद्यमियों का विश्वास उठने का भी एक बड़ा कारण थी। उदय सामंत ने आरोप लगाया कि इस वजह से कारोबार के लिए सुरक्षित स्थान समझी जाने वाली मुंबई की छवि भी खराब हुई है। उन्होंने कहा कि सचिन वझे को ठाकरे सरकार के जबरदस्त समर्थन ने उद्यमियों और निवेशकों के मनोबल को खत्म कर दिया था और इस

वजह से बड़े व्यापारियों ने महाराष्ट्र से बाहर जाने का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य से उद्योगों को बाहर निकालने में ठाकरे सरकार ने प्रमुख भूमिका निभाई। बड़ी परियोजनाओं का राजनीतिकरण करने के बजाय, उन्हें राज्य सरकार में निवेशकों का विश्वास खोने के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र से वेदांत फॉक्सकॉन, एयरबस टाटा और बल्क ड्रग पार्क जैसे बड़े बाहर चले गए है, इसके लिए पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की पिछली महाविकास आघाडी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार के दौरान, आदित्य ठाकरे ने मुंबई की प्रमुख परियोजनाओं जैसे कारशेड, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश की।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : रविवार 29 अक्टूबर 2023

टमाटर के बाद अब 50 फीसदी तक महंगा प्याज

मुंबई : हर वर्ष आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इससे निपटने के लिए वित्त वर्ष २०१८-१९ के बजट में केंद्र सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप (टोमैटो-ऑनियन-पोटैटो) के वैल्यू चेन को डेवलप करने के लिए ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन का एलान किया था, जिसके लिए ५०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये योजना फेलियर साबित हुई। बता दें कि टमाटर के बाद अब प्याज के दाम लोगों के आंखों से आंसू निकालने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली के रिटेल मार्वेष्ट में प्याज ५० से ६० रुपए प्रति किलो में मिल रहा है, जबकि एक हफ्ते पहले ३० से ४० रुपए प्रति में प्याज मिल रहा था। एक सप्ताह में ५० फीसदी तक प्याज महंगा हो चुका है। दिसंबर में नए फसल के आने से पहले महंगे प्याज से राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने अपने बफर स्टॉक से एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए प्याज बेचने का एलान किया था। सरकार प्राइस स्टैबलाइजेशन फंड के जरिए प्याज का बफर स्टॉक भी खड़ा किया है, जिससे प्याज की कीमतों में तेज उछाल से आम उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। प्याज के एक्सपोर्ट पर नकले कसने के लिए ४० फीसदी का एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया गया, इसके बावजूद प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है।

'क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलने की बीमारी है',

शरद पवार पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत ने कसा तंज

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शरद पवार पर तंज कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है. संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि 'क्या पीएम भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं.' दरअसल यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर टिप्पणी करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सक्रिय रूप से किसानों को सशक्त बना रही थी, तो महाराष्ट्र में कुछ व्यक्ति प्रतिनिधित्व की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए थे.

संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे. इस दौरान वह सिर्फ कृषि मंत्री की भूमिका में नहीं रहे, वह एक विशेषज्ञ थे, जो कृषि क्रांति के लिए जाने जाते हैं. संजय राउत का कहना है कि शरद पवार ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है. इसके साथ ही उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है.

इसके साथ ही संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को भी अपने निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी शरद पवार पर टिप्पणी कर रहे थे तो उन्हें मंच छोड़ देना चाहिए था. इस दौरान संजय राउत ने कहा कि 'देश के पीएम के रूप में यह उन्हें शोभा नहीं देता. कल तक जिस शरद पवार की पीएम तारीफ कर रहे थे, आज उनकी कमियां गिना रहे हैं, क्या पीएम मोदी को भूलने की बीमारी है? जब मोदी जी गलत बोल रहे थे तो अजित पवार को मंच से चले जाना चाहिए था.'

राज्य के नेता को बदनाम करना पीएम मोदी का उद्देश्य

संजय राउत यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया लेकिन किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण के मुद्दे और मनोज जारांगे पाटिल के अनशन पर कुछ नहीं बोले. उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य के नेता को बदनाम करना था. संजय राउत का कहना है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्ट लोग शिंदे और अजित पवार उनके साथ मंच पर बैठे थे.

भाजपा को १७३ लाख करोड़ रुपए के इस कर्ज के बारे में खुलासा करना चाहिए - सुप्रिया सुले

मुंबई : २०१४ की तुलना में देश पर यह कर्ज दोगुना हो गया है। इसलिए सरकार अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं करने के लिए जनता से माफी मांगे, ऐसे शब्दों में राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। देश के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, ऐसी जानकारी सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ढोंग कितना भी छिपाया जाए, लेकिन वह कभी भी छिप नहीं सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा सरकार कितना भी चिल्लाए, लेकिन सच्चाई सामने आए बिना नहीं रहेगी, ऐसी टिप्पणी सुप्रिया सुले ने की। वर्ष २०१४ में भारत के सिर पर ५५ लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन २०२३ के अंत तक ये आंकड़ा दोगुना से भी ज्यादा १७३ लाख करोड़ हो गया। २०१४ में भाजपा ने देश पर कर्ज को चुनावी मुद्दा बनाया था।

अवैध सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ जांच के सिलसिले में मप्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ईडी के छापे

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कुछ अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ जांच के तहत मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में छापेमारी के बाद 46.5 लाख रुपये की ''बेहिसाबी'' नकदी जब्त की है।कार्रवाई शुक्रवार को शुरू की गई और इंदौर (मध्य प्रदेश), हुबली (कर्नाटक) और मुंबई में कई जगहों पर छापे मारे गए। द्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी का मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संचालन के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दायर एक प्राथमिकी से उपजा है। इसमें कहा गया है कि 'धनगेम्स' और अन्य ह्यसट्टा मटका' (सट्टेबाजी) ऐप जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मध्य प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में आम जनता को लालच देकर फंसाने के लिए संचालित किए जा रहे थे।

कृत्रिम बारिश कराने के 'क्लाउड सीडिंग' के प्रयोग से महाराष्ट्र के सोलापुर में 18% अधिक वर्षा: स्टडी

नालासोपारा : नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शाम को रोज की तरह चहल-पहल थी, तभी वायरलेस पर एक मैसेज आया। श्रीरामनगर में एक ओवर ब्रिज के पास, नाले में नायलॉन के बैग में एक लाश होने की सूचना मिली। पुलिस ने घटना-स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव पर पड़े हुए कपड़े उतारे गए, तो शर्ट के कॉलर में टेलर का नाम और पता लिखा था। चूंकि कॉलर में पिन कोड भी था, इसलिए जांच टीम को संबंधित टेलर की कमाठीपुरा वाली दुकान को ढूंढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। टेलर को शर्ट के आगे और पीछे की तस्वीरें दिखाई गईं। टेलर ने गौर से शर्ट को देखा, तो कॉलर के आगे साइड के नीचे के तीन बटन अलग से दिखे। इन बटनों के बीच का एक बटन टूटा हुआ था। इन सभी बटनों को देखते ही उसके मुंह से अपने आप नाम निकल पड़ा कृष्णा'। उसने बताया कि वह पूरा नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि यह शख्स शर्ट के तमाम बटनों के बीच कॉलर के नीचे वाले तीन-चार बटन हमेशा अलग कलर के लगवाता है। उसने यह भी बताया कि कृष्णा, मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल मालिक के यहां काम करता है। जांच टीम कुछ मिनट बाद वहां पहुंची और होटल मालिक को कृष्णा की लाश की फोटो दिखा दी। होटल मालिक ने उसे पहचान लिया और बताया कि कृष्णा चार दिन से होटल आया ही नहीं। उसके साथ भायंदर में रहनेवाला एक अन्य होटल कर्मचारी भी चार दिन से नहीं आ रहा। पुलिस का शक फिर इस दूसरे कर्मचारी पर चला गया। होटल मालिक के पास कृष्णा का पता नहीं था, लेकिन भायंदर वाले कर्मचारी का था। जांच टीम पहुंच गई उस कर्मचारी के पास और चार दिन से होटल न जाने की वजह पूछी। उसने बहुत सहज जवाब दिया कि बीमार हूं, इसलिए ड्यूटी पर नहीं जा रहा। तब उससे कृष्णा के बारे में सवाल पूछे गए। उसने बताया कि कृष्णा, नालासोपारा में किसी अंकिता (बदला नाम) के साथ रहता है, लेकिन उसे उसका पूरा पता नहीं मालूम। इस कर्मचारी के पास कृष्णा का मोबाइल नंबर जरूर था। जांच टीम ने जब इस नंबर का सीडीआर निकाला, तो उसमें कई नंबर महाराष्ट्र के बाहर के मिले। दो-तीन नंबर मुंबई और नालासोपारा के भी थे। नालासोपारा का नंबर एक महिला का था, जो तुलिंज इलाके की प्रगति नगर बिल्डिंग में रहती थी। जब इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसने साफ कहा कि वह किसी कृष्णा को नहीं जानती। उसने सबूत के तौर पर पुलिस को अपना मोबाइल सेट ही दे दिया कि आप लोग खुद चेक कर लो कि क्या उसमें कृष्णा को कभी कोई कॉल दिख रहा है? जब पुलिस नाइक किरण म्हात्रे ने इस महिला के सामने सीडीआर की डिटेल रख दी, जिसमें उसका कुछ दिन पहले का नंबर दिख रहा था, तो महिला को एकाएक याद आया कि कुछ दिन पहले अंकिता (बदला नाम) ने उससे किसी अर्जेंट कॉल करने के बहाने मोबाइल लिया था। जांच टीम जब ऊपर फ्लैट में पहुंची, तो वह बंद था। फौरन फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया।

रेलवे परियोजना को पूरा करने के लिए जिला परिषद स्कूल तोड़ा गया, स्कूल का निर्माण आज तक नहीं

पालघर : शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तमाम दावे करती रहती हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। पालघर के आदिवासी इलाकों में तो हालात यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारद हैं, जिससे यहां शिक्षा का स्तर सुधरने की बजाय दिन-ब-दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कहीं स्कूल है तो शिक्षक ही नहीं हैं और कहीं दोनों ही नहीं हैं। डहाणू के सरावली-मोरपाड़ा इलाके में करीब ५ वर्षों से रेलवे की (डीएफसीसीएल) परियोजना को पूरा करने के लिए जिला परिषद के एक सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था, लेकिन स्कूल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जिससे इस स्कूल में पढ़नेवाले नौनिहाल भीषण गर्मी में भी कंटेनरों में भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और रेलवे से स्कूल को बनाने की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेड प्रष्टेट कॉरिडोर (डीएफसीसीएल) परियोजना के लिए ५ साल पहले स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए उस स्कूल के बच्चे बीएचसीसीआईएल मुंबई द्वारा निर्मित दो कंटेनरों में पढ़ाई कर रहे हैं। कंटेनरों में चल रहे स्कूल में आनेवाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दिनों में कंटेनर लीक होते हैं और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए छात्रों की संख्या कम हो गई है। इससे गरीब छात्रों की पढ़ाई में बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और सरकारी स्कूल टूटने के बाद बन नहीं रहा है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : रविवार 29 अक्टूबर 2023

10 ग्राम चरस और होता तो...
हाईकोर्ट ने पकड़े गए आरोपी व्यवसायी को दी बड़ी राहत

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने चरस जब्ती के एक मामले में आरोपी व्यापारी को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि जब मजिस्ट्रेट के सामने दो महीने बाद चरस का वजन किया गया तो उसका वजन एक किलोग्राम से 10 ग्राम कम था। पुलिस ने व्यापारी को जब पकड़ा था तब उसका वजन 1.01 किलोग्राम था। अदालत ने मजिस्ट्रेट के सामने तौले गए वजन का संज्ञान लिया। कोर्ट ने आरोपी बिजनेसमैन को जमानत देते हुआ कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लेने में देरी पुलिस के हाथ से बाहर थी। ऐसे में जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ और आरोपी का पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं तो उन्हें जमानत दी जाती है।

10 ग्राम कम होने से मिली बेल

ब्रांदा के व्यवसायी सुनील नायक को 1.01 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने कहा निचली अदालत में वजन के तौर चरस की मात्रा एक किलो से कम थी। ऐसे में यह मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा नहीं है। नायक को अप्रैल 2022 में बांद्रा पुलिस की मादक द्रव्य निरोधक इकाई ने पकड़ा था। नायक के वकील अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष जब प्रतिबंधित पदार्थ को तौला गया तो वह कॉमर्शियल श्रेणी में नहीं आती थी। अदालत को इसी पर भरोसा करना था। एनडीपीएस एक्ट में चरस भांग के अंतर्गत आता है, इस श्रेणी में 1 किलो से अधिक को व्यावसायिक मात्रा कहा जाता है।

'अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शुरू कर दिया काम...'
एनसीपी कोटे के मंत्री का बड़ा दावा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी उनकी नाराजगी को लेकर तो कभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चचाएं तेज होती रहती हैं. अक्सर एनसीपी के कार्यकर्ता अजित पवार को भविष्य में राज्य का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बताते नजर आते हैं. ऐसे में राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने एक बार फिर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बयान दिया है. दरअसल राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम का कहना है कि उन्होंने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है. जिसके बाद से ही महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. धर्मराव बाबा अत्राम के अनुसार उन्होंने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे राज्य में दौरे करने शुरू कर दिए हैं. जिससे आगामी चुनाव में एनसीपी की सीटों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके.

राजनीति में कुछ भी हो सकताः अत्राम

बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से एक पुराना वीडियो ट्वीट किया गया था. जिसमें देवेन्द्र फड़णवीस को मैं फिर आऊंगा के संदेश के साथ देखा गया, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में बहस छिड़ गई. फिलहाल बीजेपी की ओर से उस ट्वीट को हटा लिया गया. वहीं अब एनसीपी नेता धर्मराव बाबा अत्राम का कहना है कि वह इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है.

सीटों को बढ़ाने के लिए शुरू किया काम

धर्मराव बाबा अत्राम के अनुसार महाराष्ट्र में एनसीपी की सीटों को बढ़ाने के लिए उन्होंने राज्य का दौरा शुरू कर दिया है. इस बीच उन्होंने बताया कि जल्दी ही अजित पवार विदर्भ का दौरा करेंगे. बता दें कि इससे पहले भी हाल ही में अजित पवार को मुख्यमंत्रई बनाए जाने की चर्चा के बीच धर्मराव बाबा अत्राम ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे, जिससे की अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके.

ठाणे में हुई 1.04 करोड़ रुपये की बिजली चोरी

ठाणे : महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ने ठाणे जिले के कल्याण और टिटवाला कस्बों के आवासीय इलाकों में 1.04 करोड़ रुपये की बिजली चोरी का पता लगाया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एमएसईडीसीएल की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कल्याण क्षेत्र के कल्याण (पूर्व) और टिटवाला कस्बों के आवासीय इलाकों में दो दिनों तक अभियान चलाया गया, जिसमें बिजली चोरी का पता चला। इसमें कहा गया है कि अलग-अलग अवधि में घरेलू उपभोक्ताओं के 368 स्थानों पर 1.04 करोड़ रुपये मूल्य की कम से कम 4,84,000 यूनिट बिजली चोरी हुई। विज्ञप्ति के मुताबिक, इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं पर 98 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं तथा इस महीने 27,400 बकायेदारों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है।

बंद हो जाएंगे कोविड सेंटर...
चिकित्सा उपकरणों की होगी नीलामी

ठाणे : मीरा भायंदर महानगरपालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी के संक्रमण काल में बनाए गए अस्थाई कोविड सेंटर को स्थाई रूप से बंद करने और वहां के चिकित्सा उपकरणों को नीलामी के माध्यम से विक्री करने का निर्णय लिया है। मार्च 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में मरीजों की बढ़ती संख्या और उनके उपचार के लिए अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मनपा के प्रमोद महाजन, मिनाताई ठाकरे और अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृह के इमारत में अस्थाई कोविड सेंटर का निर्माण किया गया था। इन अस्थाई कोविड सेंटरों में कोरोना बाधित मरीजों के उपचार के लिए करोड़ों रुपए के चिकित्सा उपकरण खरीदे गए थे। इन अस्थाई कोविड सेंटरों में हजारों की संख्या में कोरोना मरीजों के उपचार कर उनकी जान बचाने में प्रशासन को सफलता मिली थी।

सभागृह होंगे कोविड सेंटर से मुक्त

धीरे-धीरे कोरोना महामारी पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया और करीब डेढ़ वर्षो से कोरोना का प्रभाव खत्म हो चुका हैं। जिससे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड के दौरान लगाए गए सभी कोविड नियमों के प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं। जिससे मनपा के सभागृहों में बनाए गए अस्थाई कोविड सेंटरों को स्थाई रूप से बंद कर उन सभागृहों को नागरिकों के लिए खुला करने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त संजय श्रीपतराव काटकर ने मनपा के दोनो अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर और डॉ संभाजी पानपट्टे को चिकित्सा उपकरणों को नीलाम कर सभागृहों को खाली करने का निर्देश दिया है। जिससे अब सभी सभागृह कोविड सेंटरों से मुक्त हो जायेंगे और आम नागरिक उसका उपयोग कर सकेंगे।

ठाणे में महिला का शव बरामद, गर्दन पर गला घोंटने का निशान

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ तालुका में मलंग किले के नीचे एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। हिल लाइन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की गर्दन पर गला घोंटने का निशान था। शव शुक्रवार शाम करीब छह बजे झाड़ियों में एक नाले के पास मिला। उन्होंने कहा, कुछ राहगीरों ने शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 25 से 30 वर्ष के आसपास है। अधिकारी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

ठाणे पुलिस के सौतेले व्यवहार की से नाराज भाजपा कार्यकर्ता,
DCM फडणवीस से की शिकायत

ठाणे : भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से ठाणे पुलिस की तरफ से उनके साथ किए जा रहे ह्यह्यसौतेले व्यवहार की शिकायत की है। भाजपा के कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख नरेंद्र सूर्यवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी कार्यकताओं ने फडणवीस की निजी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की। सूर्यवंशी ने दावा किया, ''हाल में एक पूर्व नगरसेवक के हमले में भाजपा का कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन ठाणे पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हमने पार्टी कार्यकताओं के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा सौतेला व्यवहार करने की शिकायत उपमुख्यमंत्री से की है। सूर्यवंशी ने कहा कि फडणवीस ने इस मामले पर गौर करने का वादा किया है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com